



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मानि वार्षिक
संस्कृत
१९९८
२३।०५।९८

सं० 111]
No. 111]

मई दिल्ली, मुधवार, मई 20, 1998/वैशाख 30, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 1998/VAISAKHA 30, 1920

वाणिज्य भंग्रालय

जांच शुरुआत की अधिसूचना

मई दिल्ली, 20 मई, 1998

विषय : जापान से एथिलीन प्रोपिलीन डायन रबड़ (ईपीडीएम) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 16/1/98—एडीडी.—मैसर्स हरदीलिआ यूनीमर्स लि. ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, उसका निर्धारण तथा वसूली एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें जापान से एथिलीन प्रोपिलीन डायन रबड़ (जिसे आगे ई.पी.डी.एम. कहा जाएगा) के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है :—

- स्थिति : भारत में ई.पी.डी.एम. का केवल एक ही उत्पादनकर्ता है, जिसमें यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता भारत में कुल घरेलू उत्पादन के एक बहुत छोटे हिस्से का उत्पादन करता है और इसीलिए, यह घरेलू उत्थोग की ओर से यह याचिका दायर करने की स्थिति में है।
- सम्मिलित उत्पाद : मौजूदा जांच में सम्मिलित उत्पाद एथिलीन प्रोपिलीन डायन रबड़ है। ईपीडीएम एक सिन्थेटिक रबड़ है और इसका प्रयोग रबड़ पर आधारित अनेक अनुप्रयोगों में किया जाता है। ईपीडीएम को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 4002.70 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।
- संबंधित देश : याचिकाकर्ता ने जापान के नियातकों द्वारा पाटन करने का आरोप लगाया है।
- सामान वस्तुएं : याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और जापान से आयात की जा रही वस्तुओं की विशेषताएं एक जैसी हैं और इसें आपस में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा रहा है। इसलिए, घरेलू उत्थोग द्वारा उत्पादित ईपीडीएम को जापान से आयातित ईपीडीएम के समान वस्तु माना गया है।
- उम्पिंग तथा डम्पिंग मार्जिन
 - (क) सामान्य मूल्य : याचिकाकर्ता ने जापान की एक प्रमुख पत्रिका द्वारा सूचित किए गए मूल्यों और जापान की एक कंपनी द्वारा सूचित किए गए मूल्यों के आधार पर जापान के घरेलू बाजार में प्रचलित ईपीडीएम के मूल्यों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जापान में ईपीडीएम के सामान्य मूल्य के संदर्भ में प्रथम दृष्ट्या प्रयाप्त साक्ष्य है।

(ख) निर्यात कीमत : यांचिकाकर्ता ने जापान टैरिफ एसोसिएशन द्वारा सूचित की गयी कीमतों के आधार पर पिछले तीन वर्षों की निर्यात कीमतों का निम्नानुसार दावा किया है :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य	दर
	कि.ग्रा.	(“ ०० येन)	येन प्रति कि.ग्रा.
1993	950284	147133	155
1994	1029062	136348	133
1995	1417440	185822	131
1996	1718975	265346	154

डोजीसीआईएस के अनुसार, अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997 की औसत कीमत 50 रु. प्रति किग्रा. की थी और अप्रैल से दिसंबर, 1997 के दौरान औसत कीमत 67 रु. प्रति किग्रा. की थी।

इस बात का प्रथम-दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि जापान में विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी ज्यादा है, जिस कीमत पर भारत को इसका निर्यात किया गया है, यह संकेत मिलता है कि जापान के निर्यातों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है।

6. क्षति : घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतक जैसे कि उत्पादन, विक्री, बाजार हिस्सा, लाभ/हानि इत्यादि सामूहिक और संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। प्रथम दृष्ट्या इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि विचाराधीन उत्पाद के निर्यात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

7. प्रतिपाठन जांच की शुरूआत : अतः प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

8. जांच की अवधि : वर्षमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 1996 से 30 सितम्बर, 1997 तक की है।

9. सूचना का प्रस्तुतीकरण: संबद्ध याने जाने वाले जापान के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित विधि से सुरक्षित सूचना तथा अपने विचार निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य मंत्रालय, पाटनरोधी प्रभाग, नई दिल्ली-110011 को भेजें। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित की गयी समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित विधि पूर्वक जांच से संबंधित अपनी सूचना भेज सकती है।

10. समय सीमा: मौजूदा जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 40 दिनों के भीतर पहुंच जाए। परन्तु, ज्ञात निर्यातकों और आयातकों, जिन्हें अलग से पत्र भेजे जा रहे हैं, को उन्हें अलग से भेजे गए पत्रों की तिथि से 40 दिनों के भीतर यह सूचना भेजी जानी आवश्यक है।

11. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण: नियम 6 (7) की शर्तों के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साथ्यों के अगोपनीय रूपान्तरण होते हैं।

12. यदि कोई पार्टी पहुंचने से मना करती है अथवा अन्यथा वह उपर्युक्त अवधि में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच में संकेतिक रूप से अड़चन डालती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है।

रत्ति विनय ज्ञा, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1998

Subject: Initiation of anti dumping investigation concerning import of Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM) from Japan.

No. 16/1/98-ADD:—M/s Herdillia Unimers Ltd. has filed a petition in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Ethylene Propylene Diene Rubber (hereinafter referred to as EPDM) from Japan and requested for anti dumping investigations and levy of anti dumping duties.

1. **Standing:**—There is only producer of EPDM in India, who has filed the present petition. The petitioner accounts for a major proportion of the total domestic production in India and, therefore, satisfy the standing to file the present application on behalf of the domestic industry.

2. **Product Involved:**—The product involved in the present investigation is Ethylene Propylene Diene Rubber. EPDM

is a synthetic rubber and is used in a number of rubber based applications. EPDM is classified under custom sub-heading no. 4002.70 of the Customs Tariff Act. The classification is, however, indicative only and in no way binding on scope of the present investigations.

3. Country(ies) involved: The petitioner have alleged dumping by the exporters from Japan.

4. Like Goods: The petitioner have alleged that goods produced by them have characteristics similar to the goods being imported from Japan and the two are being consumed interchangeably. EPDM produced by the domestic industry has, therefore, been treated as like article to the EPDM imported from Japan.

5. Dumping and Dumping Margin:

(a) **Normal Value:** The petitioner have furnished evidence of price of EPDM prevailing in the domestic market in Japan, based on the prices reported by a leading magazine in Japan and prices reported by a company in Japan. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to normal value of EPDM in Japan.

(b) **Export Price:** The petitioner has claimed the following export prices for the past three years, based on prices reported by Japan Tariff Association:

Year	Volume (kgs.)	Value ('000 Yen)	Rate Yen per kg.
1993	950284	147133	155
1994	1029062	136348	133
1995	1417440	185822	131
1996	1718975	265346	154

As per DGCIS, the average price for April, 1996 to March, 1997 was Rs. 50 per kg. and was Rs. 67 per kg. during April to Dec., 1997. The petitioner has claimed price adjustments on account of ocean freight, inland freight in Japan, insurance, and packing expenses. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to export price of EPDM in Japan.

There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the product under consideration in Japan is significantly higher than the price at which it has been exported to India, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from Japan.

6. Injury: The various economic indicators relating to domestic industry such as production, sales, market share, profit/loss etc. collectively and cumulatively, *prima facie*, indicate that the domestic industry has suffered material injury. There is sufficient *prima facie* evidence that the imports of the product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

7. Initiation of Anti-Dumping Investigation: The Authority, therefore, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the said country.

8. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 1996 to 30th Sept., 1997.

9. Submission of Information: The exporters in Japan and the importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Anti Dumping Division, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

10. Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.

11. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

12. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

RATHI VINAY JHA, Designated Authority

